भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने सुनिश्चित आजीवन आय के लिए पेश किया स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान

यह सेवानिवृत्ति-केंद्रित एन्युटी योजना ग्राहकों को चुनिंदा विकल्पों के तहत 2, 3 या 5 साल की लचीली प्रीमियम भुगतान शर्तों और 7 साल तक के डेफरमेंट विकल्पों के साथ, लंबे समय तक भुगतान किए बगैर, जीवन की दूसरी पारी आश्वस्त तरीके से जीने में मदद करती है। गुवाहाटी, फ़रवरी 2, 2026ः भारत की अग्रणी निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने आज भारती एक्सा लाइफ स्वाभिमान सेवानिवृत्ति प्लान (योजना) लॉन्च करने की घोषणा की। यह नॉन-लिंक्ड, गैर भागीदारी वाली व्यक्तिगत डेफर्ड एन्युटी है जिसे आजीवन सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। यह प्लान लोगों को आत्मविश्वास और वित्तीय गरिमा के साथ बेफिक्र होकर सेवानिवृत्त होने में मदद करता है। स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान ग्राहकों को जल्दी योजना बनाने और मौजूदा स्तरों पर एन्युटी दरों को लॉक करने में मदद करता है, जिससे जीवन भर के लिए गारंटीशुदा आय सुनिश्चित होती है। यह योजना आजीवन एन्युटी भुगतान प्रदान करता है, जिसमें जीवित पति या पत्नी के लिए आजीवन उसी सुनिश्चित आय को जारी रखने का विकल्प होता है। इस तरह पॉलिसीधारक या पति/पत्नी में से किसी एक भी के भी जीवित रहने तक आय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सरलता और लचीलेपन को ध्यान में रखकर तैयार यह आत्मनिर्भर विकल्पग्राहकों को आपात स्थिति में पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। प्लान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, हर 5 साल के बाद बढ़ा हुआ भुगतान ताकि ग्राहकों को महंगाई से निपटने और अपने वित्तीय लक्ष्यों, नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों के अनुरूप सेवानिवृत्ति आय को व्यवस्थित करने में मदद मिल सके। सेवानिवृत्ति योजना से जुड़े कर लाभ धारा 80सी, 80सीसीसी के तहत आते हैं जिनकी कुल सीमा 1.5 लाख है। भारती एक्सा लाइफ स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः लचीला प्रीमियम भुगतान और डेफरमेंट विकल्पः चुनिंदा एन्युटी विकल्पों के तहत 2, 3 और 5 साल के प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के विकल्प, साथ ही 7 साल तक के डेफरमेंट विकल्प, जो ग्राहकों को कम भुगतान प्रतिबद्धताओं के साथ सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद करते हैं।

आपात स्थिति में सरेंडर मूल्य निकालने का विकल्पः सारे प्रीमियम के भुगतान के बाद, पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक, सरेंडर मूल्य का एक हिस्सा निकालने का विकल्प। गारंटीशुदा आजीवन आयः एन्युटी खरीदने के बाद जीवन भर सुनिश्चित एन्युटी भुगतान। संयुक्त लाइफ एन्युटी विकल्पः यदि पॉलिसीधारक के पति/पत्नी से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तो उनके लिए निरंतर सुनिश्चित आय। प्रीमियम भुगतान में लचीलापनः एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करने या चुनिंदा एन्युटी विकल्पों के तहत 2 या 3 साल की छोटी प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) चुनने का विकल्प। लचीला भुगतानः मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक, या वार्षिक पेंशन भुगतान। डेफर्ड एन्युटी विकल्पः पेंशन कब शुरू होगी, यह तय करने की सुविधा।

आर्थिक सर्वेक्षण में सेहत की चिंता

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 में चेतावनी दी गई है कि 2035 तक भारत में 83 लाख तक बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट से पहले संसद में यह सर्वेक्षण पेश किया। इस दस्तावेज़ में अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आधिकारिक आकलन और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने एक गंभीर चेतावनी दी है, जो खाना आज हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वही कल करोड़ों बच्चों की सेहत और देश की आर्थिक मजबूती के लिए खतरा बन सकता है। पहली बार मोटापे और अनहेल्दी डाइट को सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं, बल्कि आर्थिक जोखिम के रूप में देखा गया है। यह चेतावनी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं और क्यों। वास्तव में, देश में आज बच्चों की थाली सिर्फ घर का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के भविष्य और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गई है।

तेज रफ्तार से भागती जिंदगी, काम का दबाव और आसान विकल्पों की तलाश ने माता-पिता को पैकेट बंद और रेडी-टू-ईट खाने की ओर मोड़ दिया है। चिप्स, बिस्किट, शुगरी ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स और फास्ट फूड अब बच्चों की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनते जा रहे हैं. इन्हें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड यानी यूपीएफ कहा जाता है, ऐसे फूड्स जिनमें ज्यादा शुगर, नमक, अनहेल्दी फैट और केमिकल एडिटिव्स होते हैं, लेकिन पोषण बहुत कम होता है। यूपीएफ का अत्यधिक सेवन सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है और मधुमेह (डायबिटीज), हृदय रोग और हाइपरटेंशन जैसे गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) का खतरा बढ़ रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत में 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुष ओवरवेट या मोटापे का शिकार हैं। बच्चों में स्थिति और भी चिंताजनक है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेट होने की दर 2015-16 में 2.1 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। संख्या में देखें तो 2020 में करीब 33 करोड़ बच्चे मोटे थे और अनुमान है कि 2035 तक यह आंकड़ा 83 करोड़ तक पहुंच सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में आहार संबंधी सुधारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बताई गई है। भारत यूपीएफ की बिक्री के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। सर्वेक्षण बताता है कि भारत में यूपीएफ का बाजार तेजी से बढ़ा है। साल 2006 में जहां इसकी रिटेल बिक्री लगभग 0.9 बिलियन डॉलर थी, वहीं 2019 तक यह बढ़कर करीब 38 बिलियन डॉलर हो गई। यह बढ़ोतरी सिर्फ़ बाजार का आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलती खान-पान की आदतों का सबूत है। ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने को मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियों, सांस की समस्याओं और मेंटल डिसऑर्डर्स से जोड़ा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण साफ कहता है कि इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। इससे घरों और सरकार दोनों के लिए हेल्थ केयर खर्च बढ़ेगा। लंबी बीमारियों के कारण काम करने की क्षमता घटेगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी और पब्लिक फाइनेंस पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए मोटापे को मानव पूंजी के लिए खतरा बताया गया है।

इस समस्या से निपटने के लिए, सर्वेक्षण में विद्यालय स्तर पर हस्तक्षेप की सिफारिश की गई, जिसमें पीने के पानी की

उपलब्धता में सुधार, मुफ्त फल उपलब्ध कराना, कैंटीन में केवल स्वास्थ्यवर्धक विकल्प सुनिश्चित करना और वेंडिंग मशीनों को हटाना शामिल है। रिपोर्ट में स्कूल कर्मचारियों के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य परिषद के गठन और स्कूल-आधारित उपायों को मजबूत करने के लिए एक लिखित स्वास्थ्य नीति लागू करने का सुझाव भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसमें अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के साथ अधिक सहयोग की सिफारिश की गई।

मोटापे को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पहचानते हुए, सरकार ने कई पहल शुरू की हैं ताकि स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक गतिविधि, खाद्य सुरक्षा और जीवनशैली में सुधार को एकीकृत करते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। पोषण अभियान एवं पोषण 2.0, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ईट राइट इंडिया, राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान - आज से थोड़ा कम जैसे कदम इन पहलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने %मोटापा रोकें, मोटापा भगाएं-मोटापा रोकने हेतु जागरूकता पहल% अभियान शुरू किया है। मन की बात मासिक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटापे की समस्या के बारे में देशवासियों से चर्चा कर चुके हैं।

आर्थिक समीक्षा में बच्चों में डिजिटल व्यसन की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर बुरा असर डाल रही है। डिजिटल व्यसन लगातार विचलन, 'नींद की कमी' और कम एकाग्रता के कारण शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यस्थल की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

विविध भारतीय एवं वैश्विक अध्ययनों ने 15-24 वर्ष के युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते व्यसन की पुष्टि की है। सोशल मीडिया के व्यसन का जुड़ाव घबराहट, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी और साइबर बुलिंग से उपजे दबाव के साथ भी है। भारतीय युवाओं को परेशान करने वाली अन्य समस्याओं में कंपल्सिव स्क्रॉलिंग, सामाजिक तुलना और गेमिंग से जुड़ी विकृतियां शामिल हैं। ये समस्याएं किशोरों में नींद की कमी, आक्रामकता, सामाजिकता में कमी और अवसाद को जन्म देती हैं।

गौरतलब है कि दुनियाभर में छोटे बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया को खतरनाक बताया जा रहा है। आस्ट्रेलिया और फिनलैंड ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के लिए जहां कानून लागू कर रखा है, वहीं फ्रांस की नेशनल असेंबली में ऐसा कानून लाने पर सहमति बनी है।

वहीं ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस इस मुद्दे पर व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे नंबर के स्मार्टफोन बाजार, भारत के लिए ये खास चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि देश में सालाना 75 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं। रिसर्च फर्म डाटारिपोर्टल के अनुसार, देश में एक अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, 50 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब यूजर, 40 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर और 48 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम यूजर हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इन एप्स पर 75 प्रतिशत से ज्यादा छोटी उम्र के यूजर्स हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण ने आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल व सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। सर्वेक्षण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्य अपने यहां छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अध्ययन कर रहे हैं।

आर्थिक सर्वे का साफ संदेश है सिर्फ कम खाओ, सही खाओ कहना काफी नहीं होगा। खाने की आदतें केवल व्यक्तिगत पसंद से नहीं, बल्कि फूड सिस्टम, मार्केटिंग और उपलब्धता से भी तय होती हैं। जरूरत है कि सरकार और समाज मिलकर फूड प्रोडक्शन, रेगुलेशन, लेबलिंग, विज्ञापन और रिसर्च के लेवल पर ठोस कदम उठाएं। नीतियां अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत घर से ही होगी। बच्चों को ताजा, घर का बना खाना, फल-सब्जियां, दालें और बैलेंस डाइट देना आज सिर्फ़ पालन-पोषण नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। क्योंकि सच यही है आज बच्चों की थाली में क्या है, वही कल भारत की सेहत और अर्थव्यवस्था तय करेगा।

रोहित माहेश्वरी स्वतंत्र पत्रकार
लखनऊ उत्तर प्रदेश

घाना के बाजार

मातृसत्तात्मक आर्थिक व्यवस्था की मिसाल

विश्वभर में कई समुदायों में मातृसत्तात्मक (Matriarchal) व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ वंश, संपत्ति और निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं के पास होता है। प्रमुख रूप से जिनमें इंडोनेशिया के मिनांगकाबाऊ, चीन के मोसुओ जनजाति, और भारत के मेघालय की खासी जनजाति भी शामिल हैं। इन समाजों में महिलाएँ परिवार की मुखिया और उत्तराधिकारी होती हैं। जुटाई जानकारी के अनुसार मिनांगकाबाऊ समाज इंडोनेशिया में है जो दुनिया का सबसे बड़ा मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, जहाँ संपत्ति महिलाओं द्वारा हस्तांतरित होती है। मोसुओ, चीन (यूनान और सिचुआन) के मोसुओ समाज को महिलाओं का साम्राज्य कहा जाता है। यहाँ 'वॉकिंग मैरिज' (walking marriage) की परंपरा है। भारत के मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में वंशावली माँ के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को संपत्ति विरासत में मिलती है। कोस्टा रिका की ब्रिब्री स्वदेशी जनजाति में महिलाएं भूमि की मालकिन होती हैं और कबीले के प्रमुख का पद महिलाओं के माध्यम से चलता है। नासो समुदाय जो पनामा और कोस्टा रिका में है वह भी खुद को मातृसत्तात्मक बताता है। घाना (अफ्रीका) का आसानते भी एक प्रमुख मातृवंशीय समूह है। घाना गणरा'य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोटे डी आइवर, उत्तर मंह बुरकिना फासो, और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से घिरा हुआ है। घाना की राजधानी अकरा है, और यह देश की सबसे बड़ा शहर भी है। पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर एक ट्रैवलर के वीडियो में घाना के एक ऐसे बाजार को नजदीक से देखा जहां बाजार की सारी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी। जिन्हें वहां मार्केट क्वीन कहा जाता है। मातृसत्तात्मक समाजों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है (matrilocal) और ब'चों का वंश माँ के परिवार से पहचाना जाता है। लेकिन घाना के मातृसत्तात्मक बाजार की मार्केट क्वीन का इनसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। मातृसत्तात्मक समाजों में, महिलाएं परिवार और समुदाय के निर्णयों में भूमिका निभाती हैं और संपत्ति की उत्तराधिकारिता भी महिलाओं के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए, भारत की खासी जनजाति और घाना के अकरन समुदाय में महिलाएं परिवार और समुदाय के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि घाना की मार्केट क्वीन महिलाएं 'बाजार' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, न कि मातृसत्तात्मक समाज की विशेषता। ये महिलाएं बाजार में अपनी शक्ति और प्रभाव का

उपयोग करती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे परिवार और समुदाय के निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। घाना में 'मार्केट क्वींस' (Market Queens) उन वरिष्ठ और प्रभावशाली महिला व्यापारियों को कहा जाता है, जो बाजारों में विभिन्न कमोडिटी समूहों (जैसे टमाटर, मक्का, या याम) का नेतृत्व करती हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में 'ओहेम्मा' (ohemma) भी कहा जाता है। वे बहुत कुशलता से बाज़ार के विशिष्ट अनुभागों का प्रबंधन करती हैं और व्यापारियों के बीच विवादों को सुलझाती हैं। बाज़ार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ग्रामीण उत्पादकों (किसानों) को शहरी बाज़ारों से जोड़ने के उपाय करती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये महिलाएं अक्सर एक अनौपचारिक बैंकिंग प्रणाली के रूप में काम करती हैं, जो छोटे व्यापारियों को ऋण और सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह ये महिलाएँ घाना के अनौपचारिक (informal) आर्थिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और पारंपरिक रूप से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के साथ बातचीत कर बाजार की सुविधाओं (साफ-सफाई, टैक्स आदि) का प्रबंधन करती हैं। घाना की अर्थव्यवस्था और वहां के बाजारों की संरचना दुनिया के सबसे दिलचस्प उदाहरणों में से एक है। यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है, यहां तक कि बाजार में सिर पर माल ढोने वाली श्रमिक महिलाएं भी बाजार में अपना पसीना बहाते जुटी होती हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर 'कायायेई' (Kayayei) कहा जाता है। 'काया' का अर्थ है 'सामान' और 'येई' का अर्थ है 'महिलाएं'। ये 'यादातर उत्तरी घाना के गरीब इलाकों से बेहतर जीवन की तलाश में दक्षिण के बड़े शहरों (जैसे अकरा और कुमासी) में आती हैं। ये महिलाएं अपने सिर पर बड़े एल्यूमीनियम के परातों (Pans) में भारी सामान, अनाज की बोरियां और खरीदे गए कपड़े लेकर चलती हैं। इनका जीवन अत्यंत कठिन होता है। वे बहुत ही कम मजदूरी पर काम करती हैं और अक्सर बाजारों के पास खुले में या झोपड़ियों में रहती हैं। घाना की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (Informal Economy) में इन महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। मार्केट क्वींस घाना के व्यापार की रणनीतिकार हैं, तो कायायेई उस व्यवस्था की मांसपेशियां। इन दोनों के बिना घाना की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का चलना लगभग असंभव है। घाना की सामाजिक और आर्थिक संरचना में वहां की मातृसत्तात्मक (Matriarchal/ Matrilineal) व्यवस्था का बड़ा महत्व हो जाता है। यह व्यवस्था न केवल परिवारों को चलाती है, बल्कि वहां के विशाल बाजारों के स्वरूप को भी निर्धारित करती है। घाना की सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन इन महिलाओं, विशेषकर 'कायायेई' (Kayayei) की स्थिति सुधारने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। चूंकि मार्केट क्वींस पहले से ही प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए सरकारी प्रयासों का मुख्य केंद्र बोझ ढोने वाली श्रमिक महिलाएं ही होती हैं। कौशल विकास और प्रशिक्षण (Kayayei Empowerment Programme) के अंतर्गत इन महिलाओं को केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर रहने से बचाने के लिए 'कायायेई एम्पावरमेंट प्रोग्राम' शुरू किया है। इसमें उन्हें सिलाई, साबुन बनाना, बेकिंग और कंप्यूटर जैसे तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं। ताकि वे बाजारों से निकलकर सम्मानजनक और कम जोखिम वाले व्यवसायों में जा सकें। कायायेई अक्सर खुले आसमान के नीचे या असुरक्षित बस्तियों में सोती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अकरा और कुमासी जैसे बड़े शहरों में इनके लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण शुरू किया है। यहाँ उन्हें सुरक्षित रहने की जगह, पानी और स्व'छता की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार इन महिलाओं का 'नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम' (NHIS) में मुफ्त या रियायती दरों पर पंजीकरण कराती है ताकि बीमारी की स्थिति में उनका इलाज हो सके। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी इन महिलाओं को मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ने के लिए मोबाइल मनी और छोटे बचत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2017 में घाना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कायायेई पर लगने वाले 'मार्केट टोल' (प्रतिदिन का कर) को खत्म कर दिया था। इससे उनकी दैनिक आय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले उन्हें अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा नगर पालिका को देना पड़ता था। बाजारों में काम करने वाली महिलाओं के ब'चों के लिए 'डे-केयर सेंटर' और स्कूलों में नामांकन की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उनकी अगली पीढ़ी को इस कठिन श्रम चक्र से बाहर निकाला जा सके। घाना में अब कई महिलाएं 'मार्केट क्वींस' के नेतृत्व में डिजिटल साक्षरता भी सीख रही हैं ताकि वे व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के जरिए अपने माल का ऑर्डर ले सकें। घाना के प्रसिद्ध बाजारों (जैसे कि अकरा का मकोला मार्केट) में महिलाओं का वर्चस्व इतना अधिक है कि इसे अक्सर 'मातृसत्तात्मक' आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वहां मार्केट क्वींस (Ohemmaa) न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक नियमों को भी नियंत्रित करती हैं। ऐसे में पुरुषों की भूमिका पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि वह मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, भारी श्रम और थोक आपूर्ति तक सीमित होती है। घाना के बाजार में एक अनकहा नियम हैः महिलाएं व्यापार का चेहरा हैं, और पुरुष उसकी मांसपेशियों (शक्ति) का काम करते हैं। वहां पैसा और बाजार की राजनीति महिलाओं के हाथ में होती है, जबकि पुरुष उन सेवाओं को प्रदान करते हैं जिनके बिना बाजार चल नहीं सकता। घाना में बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक जीवित प्रयोगशाला है, जहाँ मातृसत्तात्मक मूल्यों ने महिलाओं को 'शक्ति' (Power) और 'पूंजी' (Capital) दोनों दी हैं।

ब्रजेश कानूनगो

दुनिया का दादा समझने वाले की दादागिरी !

अमरीका के वर्तमान अध्यक्ष रोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना बे-बुनियाद बातें करते रहते हैं। न सिर्फ़ समस्त संसार के लिए, बल्कि खुद अमरीका के लिए भी सरदर्द बनते जा रहे हैं। वहां की जनता उनकी उल-जलुल बातों, निर्णयों से तंग आ चुकी है। वहां की कोर्ट ने भी उनको समझाने-चेताने की भरपूर कोशिश की है। सोशल मीडिया पर इसके पहले शायद ही किसी अमरीकी राष्ट्रपति पर इतने करारे कटाक्ष और कार्टून बनाए गए होंगे। भारत आदि देशों पर नित नए टैरिफ की घोषणा करना और बार-बार नोबल पुरस्कार पाने के लिए दिए जाने वाले उनके बयान हास्यस्पद लगते रहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ट्रंप से अधिकतर देश खार खाए बैठे हैं। युरोपिय देशों ने उनसे कारोबार समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। दरअसल अमरीका एक विशुद्ध व्यापारिक देश है। भिन्न-भिन्न राष्टों को आपस में उलझाना-डराना-धमकाना और अपने लाभ के लिए हथियार बेचना, यही एकमात्र उद्देश्य है इनका। अमरीका के लिए असुरक्षित बताकर छोटे-छोटे देशों पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करने की उनकी मंशा, दुनिया के लिए किरकिरी साबित हो रही है। चुनाव जीतने के दौरान उनका सच्चा साथ निभाने वाले अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने भी उनसे कन्नी काट ली है। हाल ही में उनके बोर्ड ऑफ पीस पर भी वे तंज कस चुके हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमरीका सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी कर्ज 38.3 ट्रिलियन डॉलर के आश्चर्यचकित करने वाले स्तर पर पहुंचा है। खुद को महाशक्ति कहलाने वाला, कर्जा उठाने के मामले में भी निर्विवाद रूप से नंबर 1 पर पहुंच चुका सत्य है। ताझा समाचारनुसार ट्रंप ने भारत पर 25 त्न के बदले 18 त्न टैरि टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब समय आ गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति अपने बयानों को उलटने-पलटने, दूसरे देशों को अपना शत्रु बनाने की बजाय सिर्फ़ अमरीकी हित में सोचें तो बेहतर होगा।

अशोक वाधवाणी
गांधी नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

पाटोत्सव ब्रजभाषा समारोह 8, 9 फरवरी को नाथद्वारा में

नाथद्वारा । साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा की ओर से आगामी 8 एवं 9 फरवरी 26 को नाथद्वारा के भगवती प्रसाद देवपुरा प्रेक्षागृह में दो दिवसीय पाटोत्सव ब्रजभाषा समारोह का आयोजन किया जाएगा। संस्था के प्रधानमंत्री श्याम प्रकाश देवपुरा ने बताया कि समारोह के विभिन्न सत्रों में उपनिषद में विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों के साथ विचार मंथन किया जाएगा। बृज भाषा कवि सम्मेलन, पुस्तकों के लोकार्पण के साथ - साथ 103 साहित्यकारों, पत्रकारों और प्रतिभावान विद्यार्थियों को अलंकरणों और मानद उपाधियों से विभूषित कर सम्मानित किया जाएगा।

श्याम देवपुरा ने बताया कि दो सत्रों में आयोजित ब्रजभाषा उपनिषद में भक्त कवि कुंभनदास के काव्य में दर्शन पर वृंदावन के गोपालकृष्ण दुबे, भक्त कवि सूरदास के काव्य में दर्शन पर वृंदावन के ब्रजभूषण चतुर्वेदी दीपक, भक्त कवि गोविंददास के काव्य में दर्शन पर भरतपुर के हरिओम हरि तथा भक्त कवि नंददास के काव्य में दर्शन पर

राया - मथुरा की श्रीमती संतोष ऋचा अपना व्याख्यान देंगे। उपनिषद के दूसरे सत्र में भक्त कवि छीत स्वामी के काव्य में दर्शन पर भरतपुर के सुरेश कुमार शर्मा, भक्त कवि परमानंददास के काव्य में दर्शन पर कासगंज के श्रीकृष्ण शरद, भक्त कवि चतुर्भुज दास के काव्य में दर्शन पर भरतपुर के नरेन्द्र निर्मल तथा भक्त श्रीकृष्णदास के काव्य में दर्शन पर कोटा के सत्येन्द्र यादव व्याख्यान देंगे। साथ ही समस्यापूर्ति कार्यक्रम में आमंत्रित साहित्यकारों द्वारा कवित एवं सवैया पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि भरतपुर के हरिओम हरि ,नरेंद्र निर्मल तथा डीग के सुरेन्द्र सार्थक एवं राया के अंजीव रावत को बृज ग़ज़ल श्री की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। बीकानेर के चेतन स्वामी एवं सेलम के एम. श्रीधर को साहित्य मर्मज्ञ की मानद उपाधि के साथ पांच हजार रुपए से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली की भावना शुक्ल को हिंदी साहित्य शिरोमणि एवं आगरा के रमेश पंडित को बृज भाषा मनीषी की उपाधि से विभूषित एवं तीन हजार एक सौ रूपये से सम्मानित किया जाएगा।

श्याम देवपुरा ने बताया कि रविपुरोहित बीकानेर, देवी कारफरमा कोलकाता, डॉ. सुरेश वशिष्ठ गुरुग्राम, डॉ. मंजरी पाण्डेय वाराणसी, बसंत सिंह सोलंकी उदयपुर, डॉ. विजय लक्ष्मी अल्मोड़ा, डॉ. रामकुमार घोटड़ सादुलपुर को भगवती प्रसाद देवपुरा स्मृति सम्मान तथा हिंदी साहित्य विभूषण की मानद उपाधि, डॉ. गुलाबचंद एन पटेल गांधीनगर, प.रामेश्वर दयाल महेरे शूकरक्षेत्र सिरोंज को समाज सेवा मर्मज्ञ मानद उपाधि एवं अमित गोयल राया को रक्तदान वीर मानद उपाधि एवं दो हजार एक सौ रूपये राशि से सम्मानित किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद शान्तेय झालावाड़, आनंद शर्मा दिल्ली, डॉ. महामाया प्रसाद चौबीस उदयपुर, माताप्रसाद शुक्ल ग्वालियर, डॉ. गिरी गिरिवर कोटा, अक्षयलता शर्मा जयपुर को हिंदी साहित्य मनीषी, शिवदान सिंह राणावत उदयपुर, ऋतु चतुर्वेदी भीलवाड़ा, डॉ. छगनराज राव दीप एवं डॉ. दीपा परिहार दीप्ति जोधपुर को हिंदी काव्य मनीषी अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा राजेंद्र केशोरिया,देवकी केशोरिया मथुरा, कृष्ण कुमार सेनी दौसा, डॉ. देवराज शर्मा पाली, नंदकिशोर काबरा उदयपुर एवं सुश्री उमा शर्मा मथुरा को समाज सेवा कला सेवा रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

समारोह में पत्रकारिता सेवा में लगे नाथद्वारा , ककरोली, राजसमंद क्षेत्र के 38 पत्रकारों को पत्रकार श्री की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इनमें पत्रकार गिरीश पालीवाल, दर्पण पालीवाल, गिरीराज सोनी, निलेश पालीवाल, अरविंद मुखिया, सुधीर पुरोहित, चेतन उपाध्याय, मयंक सनाढ्य, अब्दुल समद राही, दरियाव सिंह गोरवा,

प्रमोद जोशी, गोविन्द त्रिपाठी, तरूण सोनी, चिराग माहेश्वरी, जगदीश सोनी, नवीन सनाढ्य, भूपेश दुर्गावत, जगदीशचन्द्र कपूर, सत्यदेव उपाध्याय, अशोक त्रिपाठी, रामकिशन सोनी, महेश शर्मा, मनीष पुरोहित, शेखर पालीवाल, दिनेश श्रोत्रिय, तरूण दवे, सुरेशचन्द्र भाट, जुजर हुसैन, जगदीश पालीवाल, नरेन्द्र पालीवाल राजूभाई, महेश पालीवाल, तुलसीदास सनाढ्य, हेमत कुमार पालीवाल जोनू, शशि महाकाली, राहुल कपूर, कुलदीप शर्मा, दिनेश माली एवं परेश पण्ड्या को सम्मानित किया जाएगा।

प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभावान विद्यार्थियों को विद्यार्थी रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनमें डॉ. फाल्गुन पुरोहित, गौरी चौधरी, करण बागोरा, हार्दिक जोशी,मानस बागोरा, महेश माली, मयंक जोशी, ललिता वैरागी, मनन बोहरा, तितीक्षा माली, श्रीजीका सोनी, ऋषिराज सिंह, वैष्णवी परिहार, एंजल गुर्जर, गायत्री भाटिया ,आरूषी दुर्गावत , अनुकृति नैनवा , माद्री सिंह एवं पोषिता माली को सम्मानित किया जाएगा।

बाहर से सम्मान प्राप्त करने के किए आने वालों के लिए पूर्व सूचना पर आवास और भोजन की निशुल्क व्यवस्था साहित्य मंडल द्वारा की जाएगी।

डॉ. प्रभात कुमार सिंघल
लेखक एवं पत्रकार, कोटा